

ऑनलाइन गेमिंग पर नैतिक परिप्रेक्ष्य

प्रलिस के लिये:

[ऑनलाइन गेमिंग पर GST](#)

मेन्स के लिये:

भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मुद्दे।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र के पुणे में एक पुलिस उप-नरीकषक (Police Sub-Inspector- PSI) के नलिंबन का हालिया मामला सामने आया है जो [ऑनलाइन गेमिंग](#) तथा एक [कानून प्रवर्तन अधिकारी](#) के उत्तरदायित्वों से संबंधित जटिल नैतिक चिंताओं को उजागर करता है।

ऑनलाइन गेमिंग में अधिकारी की भागीदारी से संबंधित नैतिक नहितार्थ क्या हैं?

■ ऑनलाइन गेमिंग में अधिकारी की भागीदारी के पक्ष में तरक:

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार: अधिकारी को किसी भी अन्य नागरिक की तरह मलिनने वाले व्यक्तिगत समय के दौरान कानूनी मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है।
 - ऑनलाइन गेमिंग सहित कानूनी मनोरंजक गतिविधियों के लिये अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत नधिका उपयोग उनके वविकाधीन वय एवं वतिलीय स्वायत्तता के अंतरगत आता है।
- कानूनी मानदंडों का पालन: यदि ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि कानूनी रूप से स्वीकार्य है तथा वह अधिकारी कानून का अनुपालन करता है तो उनकी भागीदारी कानूनी मानदंडों के ढाँचे के भीतर है और व्यक्तिगत स्वायत्तता के भाग के रूप में इसका सम्मान किया जाना चाहिये।
- तनाव का शमन: ऑनलाइन गेमिंग किसी भी अवकाश गतिविधि की तरह तनाव से राहत देने वाले उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है, जो नौकरी के दबाव से उत्पन्न मानसिक तनाव से मुक्ति प्रदान करता है।

■ शामिल नैतिक मुद्दे:

- संगठनात्मक मानकों का उल्लंघन:
 - आचार संहिता का उल्लंघन: यूनटि कमांडर की अनुमति के बनिा ऑनलाइन गेमिंग में संलग्न होना महाराष्ट्र राज्य पुलिस के भीतर स्थापित आचार संहिता का उल्लंघन है, जो संस्थागत नियमों की उपेक्षा का संकेत देता है।
 - व्यावसायिक मानदंडों के साथ संघर्ष: नैतिक रूप से ड्यूटी के दौरान ऑनलाइन गेमिंग में अधिकारी की भागीदारी कानून प्रवर्तन के लिये आवश्यक अपेक्षित व्यावसायिकता और नैतिक मानकों के साथ संघर्ष करती है।
- नकारात्मक लोक छवि और वशिवास के नहितार्थ:
 - लोक धारणा और वशिवास का क्षरण: वर्दी में व्यक्तिगत जीत पर चर्चा वाला मीडिया साक्षात्कार अधिकारी की पेशेवर ईमानदारी और कानून प्रवर्तन की व्यापक छवि में जनता के वशिवास को कमजोर कर सकता है, जिससे जनता का पुलिस बल में वशिवास कम हो जाता है।
 - संगठनात्मक वशिवासनीयता पर प्रभाव: नैतिक रूप से ऐसे आचरण से पूरे पुलिस बल की वशिवासनीयता और प्रतषिठा को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि अधिकारी के कार्य संस्था को प्रतबिबिति करते हैं, जिससे इसकी समग्र छवि और सार्वजनिक वशिवास पर प्रभाव पड़ता है।
- रोल मॉडल अपेक्षाएँ और नैतिक ज़मिमेदारियाँ:
 - एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में भूमिका: नैतिक रूप से एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में अधिकारी एक सार्वजनिक व्यक्ति होता है और उससे नैतिक व्यवहार तथा ज़मिमेदार आचरण का उदाहरण स्थापित करते हुए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करने की उम्मीद की जाती है।

ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े व्यापक नैतिक मुद्दे क्या हैं?

- **लत और मानसिक स्वास्थ्य:** कुछ ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की लत लगने की प्रकृति से चर्चा उत्पन्न होती है, जो संभावित रूप से बाध्यकारी व्यवहार, ज़िम्मेदारियों की उपेक्षा और **मानसिक स्वास्थ्य** पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- **वित्तीय जोखिम और भेद्यता:** व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर जनसांख्यिकी, को **वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है**, जिससे गेमिंग पर अत्यधिक खर्च के कारण **कर्ज़ या आर्थिक कठिनाई** जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा **ज़िम्मेदार उपभोक्ता जुड़ाव और देखभाल के कॉर्पोरेट कर्तव्य के बारे में नैतिक सवाल उठ सकते हैं**।
- **कमजोर उपयोगकर्ताओं का शोषण:** संवेदनशील उपयोगकर्ताओं के संभावित शोषण के बारे में नैतिक चर्चा सामने आती है, जिन्हें सुरक्षात्मक उपायों एवं **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, उनके संसाधनों से अधिक व्यय करने का लालच दिया जा सकता है।
- **नियामक अस्पष्टता एवं कानूनी परभाषाएँ:** कौशल-आधारित गेमिंग तथा जुए के बीच अंतर में स्पष्ट परभाषाओं का अभाव है, जिससे इन गेमिंग गतिविधियों की प्रकृति के बारे में नियामक अस्पष्टता, नैतिक बहस के साथ-साथ इसकी विभिन्न व्याख्याएँ की जाती हैं।
- **कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व एवं उपयोगकर्ता कल्याण:** गेमिंग कंपनियों की नैतिक ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि उनके प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं का शोषण न करें तथा नशे अथवा लत वाले व्यवहार को बढ़ावा न दें और लाभ के उद्देश्यों से अधिक उपयोगकर्ता के कल्याण को प्राथमिकता दें।
 - नैतिक विचार ज़िम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने, उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने एवं इसकी लत की रोकथाम तथा समर्थन के लिये संसाधनों के प्रस्तुतिकरण से आपस में संबद्ध हैं।
- **सामाजिक मानदंडों पर प्रभाव:** जब अत्यधिक गेमिंग व्यवहार समाज में आम हो जाता है, तब नैतिक उलझनें उत्पन्न होती हैं जो सामाजिक मानदंडों के साथ ही व्यवहारों को भी परिवर्तित कर सकती हैं, विशेष रूप से युवा जनसंख्या में।

नोट: हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** की घोषणा की गई।

आगे की राह:

- **पेशेवरों के आचरण के संबंध में:**
 - **स्पष्ट संगठनात्मक नीतियाँ:** ऑफ-ड्यूटी आचरण के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अंतर्गत स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करना, विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित अनुमेय एवं गैर-अनुमेय गतिविधियों आदि को निर्दिष्ट करना।
 - नैतिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा: कानून प्रवर्तन कर्मियों को नैतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करके आश्वस्त करना कि जिनता उन्हें उनके कार्यों के लिये उत्तरदायी मानती है जो ऑन-ड्यूटी तथा ऑफ-ड्यूटी दोनों जगह नैतिक व्यवहार बनाए रखने के मूल्य पर जोर देती है।
 - **मज़बूत आचार संहिता: आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिये** मौजूदा आचार संहिता की समीक्षा कर उसे अधिक मज़बूत किया जाना चाहिये, जिसमें मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने, पेशेवर छुट्टी बनाए रखने एवं **वर्दी में सोशल मीडिया के उपयोग** के लिये दिशानिर्देश शामिल हैं।
 - **सहायता और परामर्श सेवाएँ:** अधिकारियों के लिये सहायता सेवाएँ एवं परामर्श प्रदान करना, उनके तनाव को दूर करना तथा उनके पेशे की चुनौतीपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तनाव को कम करने के लिये सकारात्मक प्रतिरोधी तंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में:**
 - **स्पष्ट कानूनी परभाषाएँ:** **कौशल-आधारित गेमिंग** तथा **द्यूत (Gambling)** के बीच का अंतर स्पष्ट करना, राज्यों में समान रूप से नियामक उपायों का मार्गदर्शन करने के लिये सटीक कानूनी परभाषाएँ सुनिश्चित करना।
 - **सहयोगात्मक शासन और नरीक्षण:** उत्तरदायी गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने, उपयोगकर्ता सुरक्षा, गेमिंग आसक्ति की रोकथाम एवं उपयोगकर्ताओं के बीच वित्तीय जोखिमों को कम करने के उपायों पर जोर देने के लिये गेमिंग कंपनियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।
 - **व्यापक अनुसंधान और विश्लेषण:** ऑनलाइन गेमिंग के **मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों** के लिये व्यापक स्तर पर शोध में निवेश करने तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण व प्रभावी नियामक उपायों के विकास की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।